बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 190 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 29 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी उदयपुर फाइल्स में लगे छह कट, दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

नई दिल्ली। कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल टेलर मर्डर के निर्माताओं ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि फिल्म में छह कट लगाए गए हैं और फिल्म का पुनः प्रमाणन अभी लंबित है। वहीं, इस पर पीठ ने मामले की सुनवाई 30 जुलाई के लिए निर्धारित कर दी। अदालत जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और मोहम्मद जावेद (कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी) द्वारा फिल्म की रिलीज पर आपत्ति जताने वाली याचिकाओं पर विचार कर रही है। वहीं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से संपर्क करने का निर्देश दिया था।

नई दिल्ली, (ए, के, चौधरी)पार्लियामेंट हाउस में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे और नेता विपक्ष श्री राहुल गाँधी के साथ इंडिया गठबंधन के सांसद मौजूद रहे।, छाया-साहिल गौड़

मुसलमानों के खिलाफ़ बोलने की हिम्मत नहीं, राहुल-अखिलेश पर भड़के निशिकांत दुबे, कहा- ये बांग्लादेशी नागरिकों को वोटर बनाना चाहते हैं

नई दिल्ली। बिहार में एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के विरोध पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी जानते हैं कि एसआईआर क्या होता है?... जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 21 से 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, तब उन्होंने विशेष संशोधन की बात कही थी। उन्हें कानून नहीं पता। उनके पिता का कानून पास हो गया है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक जिनके नाम कट गए हैं, उन्हें अपना आवेदन जमा करने का अधिकार है। अभी फाइनल प्रिंट नहीं आया है। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट नहीं आई है। 1 सितंबर के बाद वोटर लिस्ट जारी होगी। निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर कहा कि ये चुनाव बांग्लादेश के नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों के वोटर कार्ड पर होगा। ये बांग्लादेशी नागरिकों को यहाँ वोटर बनाना चाहते हैं। ये मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज एक मौलाना अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कुछ कहता है, लेकिन इन लोगों में मुसलमानों के खिलाफ़ बोलने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के इस बयान पर कि पहलगाम के आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इसका कोई सबूत नहीं है, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक देशद्रोही संगठन बन गई है। एएनआई से बात करते हुए, भाजपा सांसद ने कहा, कांग्रेस एक देशद्रोही संगठन बन गई है। आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाली कांग्रेस का क्या वजूद है? राहुल गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उन पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी पूरा रक्षा सौदा पढ़ रहा था... आपको समझना चाहिए कि सेना के लिए तीन दिन का गोला-बारूद भी नहीं था... उदाहरण के लिए, अगर वायुसेना के प्रशिक्षण के लिए कोई विमान खरीदना होता, तो कांग्रेस 25 साल तक उस पर कोई फैसला नहीं ले पाती क्योंकि कमीशन और सौदा तय नहीं हो पाता... अगर आप राहुल गांधी से लेकर चिदंबरम तक किसी भी चीज के बारे में बयान देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अपने ही मुँह पर तमाचा मार रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बहस से पहले, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने यह आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया है कि सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर भारत की सैन्य प्रतिक्रिया की मुख्य जानकारी साझा करने में आनाकानी कर रही है। क्विंट समाचार आउटलेट को दिए 27 जुलाई के एक साक्षात्कार में, चिदंबरम ने सवाल उठाया कि क्या सरकार ने एक और पहलगाम को रोकने के लिए कोई अनुवर्ती कदम उठाए हैं।

ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? विपक्ष के यू-टर्न पर भड़के किरेन रिजिजू

नई दिल्ली।ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होने से पहले ही लोकसभा स्थगित होने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर वार किया है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस और विपक्ष अब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं?

उन्होंने कहा कि हम सभी चर्चा के लिए तैयार थे। चर्चा शुरू होने से 10 मिनट पहले, विपक्ष ने अपना एजेंडा पेश किया कि सरकार एक निश्चित समय सीमा तय करे कि इसके बाद एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा होगी। चर्चा शुरू होने से ठीक 10 मिनट पहले ऐसी शर्त लाना ठीक नहीं है। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने यू-टर्न ले लिया है।

यह नहीं चलेगा। संसद की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। रक्षा मंत्री बहस की शुरुआत करेंगे। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि वे उनकी बात सुनें। किसी भी विपक्षी दल को पाकिस्तान की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आपको बता दें कि ऑपरेशन

सिंदूर पर चर्चा शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में नारेबाजी जारी रखी। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 1:00 बजे तक स्थगित कर दी गई।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पहले आप ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की माँग करते हैं, फिर सदन में वेल में आते हैं। अगर आप चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, तो कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाएँ। क्या आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहते हैं या नहीं?... क्या मुझे सदन की कार्यवाही स्थगित कर देनी चाहिए? इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल में दोपहर 12 बजे तक स्थगित करने से पहले, अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि विपक्षी सदस्य जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के नेता (राहुल गांधी) से अनुरोध किया कि वे अपनी पार्टी के सदस्यों से पोस्टर न दिखाने को कहें। उन्होंने कहा कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन सदन की गरिमा को ठेस पहुँचा रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों को प्रश्नकाल में बोलने नहीं दिया जा रहा है और देश की जनता सब देख रही है, और सदन की कार्यवाही जानबूझकर बाधित की जा रही है। सदन की बैठक प्रारंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी दलों के सदस्य 'एसआईआर वापस लो' के नारे लगाने लगे। बिरला ने कहा, ''क्या आप सदन बाधित करना चाहते हैं, क्या ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? आप लोग आए थे और कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए...आखिर अब सदन क्यों नहीं चलने दे रहे?'' उन्होंने सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कहा, ''माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अपने नेताओं को समझाओ कि इन्हें सदन में पर्चियां फेंकने और तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा गया है।''

दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला: आप विधायक अमानतुल्लाह खान की बढ़ी मुश्किल, सीबीआई मामले में आरोप तय

नई दिल्ली। दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में अनियमितताओं से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) से विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज किया गया था। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान पर आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप तय किए हैं। जांच एजेंसी ने 31 अगस्त 2022 को आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपपत्र के मुताबिक, अमानतुल्लाह ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 2016 से 2021 के बीच नियमों को ताक पर रखकर कई अवैध नियुक्तियां कीं। जांच एजेंसी का कहना है कि इन नियुक्तियों में न तो कोई विज्ञापन निकाला गया और न ही पात्रता मानकों का पालन किया गया। सीबीआई ने इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपित बनाया है, जिनमें वक्फ बोर्ड से जुड़े कर्मचारी और फायदा पाने वाले व्यक्ति शामिल हैं। एजेंसी का कहना है कि यह भर्ती प्रक्रिया एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई थी, जिससे सरकारी पदों का दुरुपयोग हुआ। यह मामला सबसे पहले 2016 में सामने आया था और तभी से इसकी जांच जारी है। सीबीआई अपनी जांच में पाया कि अमानतुल्लाह ने अपने पद का फायदा उठाकर नियमों को दरकिनार किया और अपने पसंदीदा लोगों को लाभ पहुंचाया। फिलहाल, सभी आरोपितों पर आरोप तय होने के बाद अब इस मामले की नियमित सुनवाई शुरू होगी।

आपको पर्चे फेंकने और तख्तियां लहराने के लिए नहीं भेजा गया, राहुल-गोगोई का नाम लेकर बिफरे ओम बिरला

नई दिल्ली । संसद के मानसून सत्र में हंगामे और शोरशराबे का दौर जारी है। आज छठे दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद भी सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच का गतिरोध समाप्त नहीं हुआ। लोकसभा की कार्यवाही बाधित होने पर स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए और उन्होंने कांग्रेस सांसदों का नाम लेकर सदन में योजना बनाकर व्यवधान पैदा करने का आरोप लगाया। बिरला ने राहुल गांधी और असम से निर्वाचित सांसद गौरव गोगोई का नाम लेकर उन्हें टोका। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के हंगामे पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, मिस्टर गोगोई और आप सब राजनीतिक दलों के लोग आए थे, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, फिर आप सदन बाधित कर रहे हैं। आखिर सदन आप क्यों नहीं चलने दे रहे? प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आखिर देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों स्थगित करना चाहते हैं? क्यों आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित बाधा करना चाहते हैं? ओम बिरला ने कहा, माननीय प्रतिपक्ष के नेता.. आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है.. आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते.. जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर आज चर्चा होने वाली है। शिक्षा, पर्यावरण, विधि, श्रम जैसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा... सदस्यों का समय होता है... आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, पर्चियां फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा है आपकी। देश देखना चाहता है, आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं गरिमा को गिराते हैं आप चर्चा नहीं करना चाहते... प्रश्नकाल में माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है... आग्रह कर रहा हूं सदन की मर्यादा बनाकर रखो। सदन सबका है। देश की 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति की सर्वोच्च संस्था है। लोकसभा स्पीकर ने कहा आप इसी तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहते हैं, ये देश देखेगा कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, पर्चे फेंके, नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही स्थगित कर दी।

दिल्लीवालों की सेहत के लिए एमसीडी का बड़ा कदम, डेंगू-मलेरिया से निपटने को 3 अस्पताल अलर्ट

नई दिल्ली। डेंगू दुनिया भर के कई देशों में एक आम बीमारी है, जिनमें अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व, एशिया और प्रशांत द्वीप समूह शामिल हैं। दुनिया की लगभग आधी आबादी, यानी लगभग 4 अरब लोग, डेंगू के जोखिम वाले क्षेत्रों में रहते हैं। जोखिम वाले क्षेत्रों में डेंगू अक्सर ज्वर संबंधी बीमारियों का एक प्रमुख कारण होता है। इन क्षेत्रों में डेंगू के प्रकोप की खबरें अक्सर आती रहती हैं दिल्ली नगर निगम ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मद्देनजर तीन अस्पतालों को प्रहरी निगरानी केंद्र के रूप में नामित किया है तथा इन बीमारियों के मामलों में इस मौसम में वृद्धि को रोकने के लिए उपाय तेज कर दिये हैं। रविवार को, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने घोषणा की कि हिंदू राव अस्पताल, स्वामी दयानंद अस्पताल और कस्तूरबा अस्पताल में जरूरी इंतजाम कर उन्हें 'प्रहरी निगरानी अस्पतालों' का दर्जा दिया गया है। इन अस्पतालों में मामलों में अपेक्षित वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए समर्पित बिस्तर और विशेष संसाधन उपलब्ध होंगे। शर्मा ने बताया कि हिंदू राव अस्पताल में 70, स्वामी दयानंद अस्पताल में 22 और कस्तूरबा अस्पताल में 75 बिस्तर

आरक्षित किए गए हैं। उन्होंने कहा, ''दवाओं, अंतःशिरा द्रव्यों और प्लेटलेट समेत सभी आवश्यक चिकित्सा जरूरतें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायी गयी हैं। समय पर देखभाल प्रदान करने के लिए डॉक्टरों, नर्सों और तकनीकी कर्मचारियों की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।'' इस बीच, शहर के कुछ इलाकों में हैजा के बढ़ते मामलों को देखते हुए, एमसीडी ने असुरक्षित पेयजल वाले इलाकों में विशेष अभियान शुरू किए हैं। संक्रमण और निर्जलीकरण से बचाव के लिए तरल क्लोरीन और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरएस) के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं।

अदालत ने जस्टिस वर्मा से पूछा- पहले कोर्ट क्यों नहीं आए? नकदी विवाद पर अब 30 जुलाई को सुनवाई

नई दिल्ली । नकदी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में आंतरिक जांच समिति की उस रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने की अपील की है, जिसमें उन्हें नकदी बरामदगी विवाद में कदाचार का दोषी पाया गया है। इस सुनवाई को करते हुए जज ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और एजी मसीह की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से सवाल किया, जो याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए थे। कोर्ट ने पूछा कि आप पहले जांच समिति के सामने पेश क्यों हुए? क्या आप कोर्ट आए थे यह कहने कि वीडियो हटाया जाए? आपने जांच पूरी होने और रिपोर्ट जारी होने तक इंतजार क्यों किया? क्या आपने पहले वहां से अनुकूल आदेश पाने की उम्मीद की थी? पीठ ने यह भी कहा कि याचिका दाखिल करते समय जस्टिस वर्मा को जांच रिपोर्ट भी साथ लगानी चाहिए थी।

कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि याचिका में जिन पक्षों को शामिल किया गया है, वो सही तरीके से तय नहीं किए गए हैं। कोर्ट ने सिब्बल से कहा कि वे एक पेज का बुलेट पॉइंट सारांश तैयार करें और मेमो ऑफ पार्टीज ठीक करें। वहीं, सिब्बल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत एक न्यायाधीश को सार्वजनिक बहस का विषय नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वीडियो का सार्वजनिक होना, मीडिया में बहस और जनता में हंगामा न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है। दिल्ली में उनके सरकारी आवास से भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद की गई थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आंतरिक समिति का गठन किया था, जिसने मामले की जांच की थी। जांच में उनके खिलाफ मजबूत सबूत पाए गए थे और उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही की सिफारिश की गई थी। इस मामले में बीते 18 जुलाई को जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी और जांच समिति की रिपोर्ट को खारिज करने और देश तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की 8 मई की सिफारिश रद्द करने का अनुरोध किया था। अपनी याचिका में न्यायमूर्ति वर्मा ने दलील दी है कि जांच गंभीरता से नहीं हुई। ऐसे में उन्हें अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने और उन्हें गलत साबित करने की आवश्यकता हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पैनल के निष्कर्ष पहले से ही कल्पना की गई कहानी पर आधारित थे। न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि जांच की समय-सीमा केवल प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की कीमत पर और कार्यवाही को जल्द से जल्द से समाप्त करने की इच्छा से प्रेरित थी। याचिका में तर्क दिया गया है कि जांच पैनल ने उन्हें पूरी और निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिए बिना ही फैसला सुना दिया। याचिका को अभी सुनवाई के लिए किसी पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाना है। घटना की जांच कर रहे पैनल की रिपोर्ट में कहा गया था कि न्यायमूर्ति वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों का उस स्टोर रूम पर नियंत्रण था, जहां से भारी मात्रा में अधजली नकदी मिली थी। इससे उनके कदाचार का सबूत मिलता है, जो इतना गंभीर है कि उन्हें हटाया जाना चाहिए।

क्यों इस्तीफा देने को मजबूर हुए धनखड़?

त्रिदीप रमण

शोहरत और कामयाबी एक खुशबू की तरह होती है जो ज्यादा देर तक किसी के हिस्से टिकती नहीं, इस बात का इल्म देश के उपराष्ट्रपति रह चुके जगदीप धनखड़ को भी बखूबी हो चुका होगा, नहीं तो भाजपा के भक्ति-भाव में ओत-प्रोत होकर उन्होंने सियासी दंभ और रंगे स्वांगों से अब तक का सबसे बड़ा रंगमंच सजाया था, आज उनके इस 'सोलो प्ले' के ग्रीन रूम के उप सन्नाटे ही उन्हें काटने को दौड़ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा की ओर से उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया था, दरअसल नेताओं के संवादों की गर्मी इस कदर बढ़ गई थी कि दबाव में आकर उन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। यहां तक कि धनखड़ के इस्तीफे की बात से भाजपा हैरान थी। भाजपा के एक नेता ने उपराष्ट्रपति को फोन किया था, पर किसी कारणवश दोनों नेताओं के दरम्यान बातचीत नहीं हो पाई। दरअसल भाजपा व धनखड़ के संबंधों के दरम्यान तल्खी तब से आनी शुरू हो गई थी जब कथित तौर पर धनखड़ ने राहुल समेत अन्य विपक्षी नेताओं से अपनी दोस्ती की पींगे बढ़ानी शुरू कर दी थी। पिछले दिनों धनखड़ ने उपराष्ट्रपति रहते राहुल को अपने पास मिलने को बुलाया, कहते हैं यह मुलाकात कोई ढाई घंटे चली। धनखड़ ने राहुल के समक्ष स्पष्ट किया कि 'वे भी विपक्षी दलों से अच्छे संबंधों के पक्षधर हैं', इसके बाद ही जयराम रमेश की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों की एक टीम उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंची और तब सदन में एक बेहतर तालमेल व सौहार्द के लिए सहमति बनी। कहते हैं इस मुलाकात में जयराम इतने अभिप्रेरित थे कि उन्होंने बाहर आकर अपने नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से कह दिया कि 'आप लोकसभा देख लो, यहां (राज्यसभा में) तो सब बढ़िया हो गया है।' यह बात भाजपा तक पहुंच गई। धनखड़ यहीं नहीं रुके उन्होंने तृणमूल समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से भी मेल-जोल शुरू कर दिया। इस कड़ी में वे अरविंद केजरीवाल से भी मिले। इसके बाद धनखड़ वामपंथी रुझान रखने वाले और सत्ताधारी दल व उनके नेताओं के कटु आलोचक माने जाने वाले आधा दर्जन पत्रकारों से भी मिले, ये पत्रकार अपने स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। कई सार्वजनिक मंचों से उपराष्ट्रपति ने किसानों के हक में खुल कर बोलना शुरू कर दिया, उनके इन विचारों की तपिश सत्ताधारी दल को परेशान करने लगी थी। पिछले कुछ समय से जिस तरह धनखड़ ने न्यायपालिका को आड़े हाथों लेते हुए उसके वर्चस्व को चुनौती दी थी यह बात भी सरकार को रास नहीं आ रही थी, जब से सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस गवई ने अपना कार्यभार संभाला है सरकार कोर्ट से किसी प्रकार की कोई तकरार नहीं चाहती है। धनखड़ जस्टिस वर्मा पर महाभियोग के मामले को लेकर भी खासे उत्साहित और एक्टिव थे। चूंकि लोकसभा में यह मामला आ चुका था सो सरकार राज्यसभा में इंतजार करने के हक में थी, पर 61 विपक्षी राज्यसभा सांसदों के दस्तखत के साथ धनखड़ ने ऊपरी सदन में भी जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने की संभावनाओं के द्वार खोल दिए थे। एक तरह से यह दिल्ली के निज़ाम के समक्ष खुली चुनौती उछाल दी गई थी।

बात नड्डा से शुरू होकर दूर तलक गई

सदन में जिस अंदाज में जेपी नड्डा ने खड़गे को संदर्भित करते हुए कहा कि 'नड्डा बताएंगे कि सदन में बोला गया क्या रिकार्ड पर जाएगा या नहीं', इस बात और नड्डा के बोलने के अंदाज पर धनखड़ बेहद असहज हो गए। सूत्रों की मानें तो सत्र स्थगित होने के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति ने नड्डा को अपने कमरे में बुला कर कुछ इस अंदाज में झिड़क दिया कि 'आप कौन होते हैं मेरे अधिकार क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश करने वाले और मुझे कमांड देने वाले?' नड्डा ने यह संवाद भाजपा तक पहुंचा दिया। सूत्रों के दावों पर अगर यकीन किया जाए तो फिर वहां से सीधे धनखड़ को फोन गया और यह बातचीत का सिलसिला धीरे-धीरे झड़प की शक्ल अख्तियार करता गया। धनखड़ ने फोन के दूसरे तरफ वाले अति प्रभावशाली सत्ताधारी नेता को समझाना चाहा कि 'संवैधानिक तौर पर मैं अभी भी देश का नंबर दो हूं, आप मुझ से जूनियर हैं, आप इस टोन में मुझसे बात नहीं कर सकते।' तो दूसरी तरफ से कहा गया कि 'कल ही हम आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे तब तो आपकी कुर्सी नहीं बचेगी।' कहते हैं एक इतने ही असहज नोट पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत खत्म हो गई। इसके तुरंत बाद एक मंत्री के कमरे में भाजपा के राज्यसभा सांसदों को तलब किया गया और सादे कागज पर उनके दस्तखत ले लिए गए, उपराष्ट्रपति को जब इस बात की भनक मिली तो उन्होंने समझा कि शायद उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। संविधान के मर्मज्ञ धनखड़ जानते थे कि अगर राज्यसभा सांसद संसद में मोशन लेकर आ गए तो उन्हें अपने पद से हटना पड़ सकता है, तो घर जाकर उन्होंने इस पूरी बात की चर्चा अपनी पत्नी और बेटी के साथ की। परिवार में यह राय बनी कि पद से हटाए जाने से बेहतर होगा स्वयं ही सम्मानजनक तरीके से इस पद को छोड़ देना, और धनखड़ ने वैसा ही किया।

धनखड़ का पहला फोन जयंत को

पद से त्यागपत्र लिखने के बाद कहते हैं धनखड़ ने पहला फोन केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी को किया। सूत्रों का दावा है कि जयंत को धनखड़ अपना दत्तक पुत्र मानते हैं और उन पर आशीष स्नेह रखते हैं। माना जाता है कि पिछले चुनाव में जयंत को अखिलेश के पाले से निकाल कर भाजपा के बगलगीर करने में धनखड़ की ही सबसे अहम भूमिका थी। यह भी दावा किया जा रहा है कि अपनी अल्लसुबह ही जयंत धनखड़ से मिलने उनके घर पहुंचे और दोनों नेताओं के दरम्यान एक लंबी बातचीत हुई। यह भी माना जा रहा है कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही जाट समुदाय में भाजपा को लेकर किंचित नाराजगी और बढ़ गई है। इससे पहले भी जब जाट नेता सत्यपाल मलिक के मामले ने तूल पकड़ा था तो हरियाणा, राजस्थान व पश्चिमी यूपी के जाट बहुल इलाकों में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। कहते हैं इस 'जाट इफेक्ट' की वजह से हरियाणा की 3, राजस्थान की 7 और पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर व नगीना सीट भाजपा को गंवानी पड़ी थी। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में भाजपा के विजयी उम्मीदवारों की जीत का अंतर भी कम हो गया था। अब देखना है कि इन नई परिस्थितियों में धनखड़ कितने दिनों तक अपने को चुप्पी के ओढ़े आवरण में रख पाते हैं।

राहुल का धनखड़ प्रेम

इसी शुक्रवार को राहुल गांधी ने धनखड़ साहब को फोन कर पहले तो उनका खैर मकदम पूछा, फिर कहा-'बड़े दुख की बात है कि सरकार आपके लिए कोई फेयरवेल ही नहीं रख रही है, सो हमने 25-26 विपक्षी पार्टियों ने मिल कर तय किया है कि हम आपके सम्मान में दिल्ली के अशोक होटल में एक फेयरवेल कार्यक्रम रखेंगे, इसमें सदन को दिए गए आपके योगदानों की चर्चा करेंगे।' कहते हैं धनखड़ पहले तो इस प्रस्ताव पर थोड़े भावुक हुए, फिर खुद को संयत करते हुए कहा-'मैं आपका दिल से आभारी हूं, आपका और तमाम विपक्ष का कि आप लोगों ने मेरे लिए ऐसा सोचा, पर मैं इस पूरे मामले को कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता, क्योंकि आप इस कार्यक्रम में पीएम को तो आमंत्रित करेंगे नहीं?' राहुल ने कहा-क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, पर आना न आना उनकी मर्जी। जैसे ही राहुल की इस पहल की खबर तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी को लगी उन्होंने फौरन खड़गे को फोन कर हड़का दिया और कहा-राहुल जी हर जगह तृणमूल का नाम ले लेते हैं, पर धनखड़ जी को फेयरवेल देने के कार्यक्रम रखने में हमारी सहमति क्यों नहीं ली गई? जाहिर है इस पर खड़गे से कोई जवाब देते नहीं बना।

थाईलैंड-कम्बोडिया संघर्ष

आज पूरी दुनिया युद्ध से गुजर रही है। यूक्रेन-रूस, इजराइल- फिलिस्तीन युद्ध जारी है। ईरान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, नाइजीरिया, इथोपिया, यमन, कांगो आदि देश या तो सीधे युद्ध में उलझे हुए हैं या फिर उनमें आतंकवाद और गृह युद्ध की स्थिति है। इनमें लाखों लोगों की मौत हो रही है। यह दृश्य अमानवीय ही नहीं बल्कि खौफ पैदा करने वाले हैं। लाखों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए हैं या फिर उन्हें अपना घर-बार छोड़कर दूसरे देशों में जाने को विवश होना पड़ा है। अमेरिका और चीन तथा अन्य बड़ी शक्तियां पर्दे के पीछे से अपना खेल खेल रही हैं। ऐसा लगता है कि अब हर कोई हिंसा में पागल हो रहा है। वैश्विक नेतृत्व नाकाम हो चुका है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। सबको अपने-अपने हितों की चिंता है। किसी को सत्ता की चिंता है तो किसी को व्यापारिक हितों की। अब एशिया के दो छोटे देश थाईलैंड और कम्बोडिया में? पिछले चार दिन से सीमा पर संघर्ष हो रहा है। इस युद्ध में 35 से ज्यादा लोग और कई सैनिक मारे गए हैं और एक लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। अब इस युद्ध में अमेरिका और चीन की भी एंट्री हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर अपना पुराना हथकंडा अपनाते हुए दोनों देशों को चेतावनी दी है कि अगर दोनों ने संघर्ष बंद नहीं किया तो सम्भावित अमेरिकी व्यापार समझौता खतरे में पड़ जाएगा। साथ ही ट्रम्प ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम की ही तरह यह दावा कर दिया है कि थाईलैंड और कम्बोडिया तत्काल बैठक करने और युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। चीन भी परोक्ष रूप से कम्बोडिया के पीछे खड़ा हुआ है। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम ने थाईलैंड की युद्धविराम की इच्छा को स्वीकार किया लेकिन कम्बोडिया पर पूरा भरोसा नहीं जताया। एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने ट्रम्प से आग्रह किया कि वह थाईलैंड की शांति के लिए दोनों पक्षों की बातचीत की इच्छा को कम्बोडिया तक पहुंचाएं। हालिया हिंसा पिछले एक दशक में थाईलैंड और कम्बोडिया के बीच सबसे गंभीर जंग है। शनिवार को झड़पें थाईलैंड के ट्राट प्रांत और कम्बोडिया के पुरसात प्रांत में तेज हो गईं। इससे प्रारंभिक संघर्ष क्षेत्र से 100 किलोमीटर दूर एक नया मोर्चा खुल गया। थाईलैंड और कम्बोडिया के बीच सीमा पर जारी विवाद का इतिहास कई सदियों पुराना है, जो मुख्य रूप से 11वीं सदी के प्रेह विहियर मंदिर और आसपास के क्षेत्रों को लेकर है। यह विवाद दोनों देशों के पुराने राजनीतिक और सांस्कृतिक दावों से जुड़ा है, जो कोलोनियल एरा के दौरान बनी सीमाओं और नक्शों की अस्पष्टता के कारण आज भी जारी है।

थाईलैंड और कम्बोडिया के बीच संबंध काफी जटिल और संवेदनशील रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर यह युद्ध क्यों हो रहा है। इस युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण प्राचीन शिव मंदिर है। प्रेह विहियर मंदिर दांगरेक पहाड़ियों में स्थित है, जिसे 9वीं से 12वीं सदी के दौरान खमेर साम्राज्य ने बनवाया था। खमेर साम्राज्य के पतन के बाद 19वीं सदी में यह क्षेत्र थाईलैंड (तत्कालीन साइएम) और फ्रांसीसी उपनिवेश कम्बोडिया के बीच विवाद का केंद्र बन गया। फ्रांसीसी और साइएम के बीच 1904 और 1907 के समझौतों के तहत सीमाओं का निर्धारण हुआ, जिसमें फ्रांसीसी नक्शाकारों ने इस मंदिर को कम्बोडिया की सीमा में रखा लेकिन सीमाओं की सही व्याख्या के लिए बनी मिश्रित कमिशन ने विवादों को पूरी तरह से सुलझाया नहीं। 1953 में कम्बोडिया की स्वतंत्रता के बाद भी यह विवाद जारी रहा। 1962 में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने फैसला सुनाया कि प्रेह विहियर मंदिर कम्बोडियाई क्षेत्र में है लेकिन मंदिर के आसपास 4.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विवाद खुला छोड़ दिया गया जिससे सीमा टकराव जारी रहा। थाईलैंड ने इस फैसले को आंशिक रूप से स्वीकार किया, जबकि वहां के राष्ट्रवादी इससे नाराज रहे। 2008 में कम्बोडिया ने प्रेह विहियर मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाया जिससे थाईलैंड में असंतोष फैला और दोनों देशों की सेनाएं विवादित इलाके में तैनात हो गईं। तब से सीमा पर कई बार हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिक मारे गए और कई परिवार विस्थापित हुए। कम्बोडिया-थाईलैंड संघर्ष से भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। इसकी अहम वजह हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा है। भारत के दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं। वियतनाम इसलिए परेशान है कि उसका कम्बोडिया और चीन के साथ सीमा तनाव का लम्बा इतिहास रहा है। अगर दोनों देशों में संघर्ष जारी रहता है तो वियतनाम की अपनी सीमा रक्षा जटिल हो सकती है। चीन के कम्बोडिया के साथ मजबूत रक्षा और आर्थिक संबंध रहे हैं।

उसने कम्बोडिया में काफी निवेश कर रखा है और वह उसे सैन्य सामग्री भी देता है। अमेरिका के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में दबदबा बनाए रखने के लिए थाईलैंड की जरूरत है और रक्षा संधि के तहत थाईलैंड उसका सहयोगी है। दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया भी इस संघर्ष को लेकर चिंतित है। हिन्द प्रशांत क्षेत्र में कोई तनाव न हो इसलिए थाईलैंड-कम्बोडिया संघर्ष खत्म होना ही चाहिए। अब समय आ गया है कि युद्ध पर सवाल उठाएं, क्योंकि युद्ध में अंततः मानवता की ही हार होती है।

'राष्ट्रीयता' का अर्थ समझें 'स्याहपोश जरनैल' से

हमें न जाने 'राष्ट्रीयता' या 'भारत माता की जय' पर मचे अनावश्यक बवाल से फुर्सत कब मिले, मगर इसे सही अर्थों में समझना हो तो दिल्ली के एक भूले-बिसरे 'स्याहपोश जरनैल' को याद कर लें। लगभग 26 वर्ष ब्रिटिश शासकों की जेल में कटे। पूरी उम्र काले वस्त्र पहने, पहले ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध रोष के लिए और बाद में साम्प्रदायिकता के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करने के लिए। यानि पूरी ज़िन्दगी व्यवस्था के खिलाफ जंग में ही गुजार दी। जी हां! शायद विश्व के स्वाधीनता-संग्रामों के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। आप शायद आसानी से यकीन न करें मगर यह तथ्य है कि स्वाधीनता सेनानियों की फहरिस्त में एक ऐसा नाम भी शामिल है जिसने अपनी सारी ज़िन्दगी में सिर्फ काले वस्त्र ही पहने। उस व्यक्ति ने अपनी जवानी का एक लम्बा हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्य की जेलों में बिताया मगर अपने वस्त्रों का रंग नहीं बदला। शहीदे आजम भगत सिंह उन्हें 'स्याह जरनैल' भी कहा करते थे।' गत दिवस हरियाणा विधानसभा की एक गैलरी से गुजरा तो नजर एक फोटो पर टिक गई। यह फोटो भारत-पाक विभाजन के समय दिल्ली में आकर बसे लाला केदारनाथ सहगल की थी। इस चित्र का अनावरण डेढ़ दशक पूर्व उस समय के मुख्यमंत्री ने किया था। चित्र देखते ही उस शख्स का व्यक्तित्व जेहन में कौंध गया। हम अक्सर कुछेक ऐसे स्वाधीनता सेनानियों को भी भुला बैठते हैं, जिनकी ज़िन्दगी का एक-एक लम्हा प्रेरक बिन्दु बन जाता है। लाला केदारनाथ सहगल स्वाधीनता संग्राम के मध्य 1911 से लेकर 1947 तक 26 वर्ष जेल रहे। एक बार तो जेल में रहते हुए ही 1945 में उन्होंने लाहौर से पंजाब विधानसभा का चुनाव भी जीता था। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद वह फरीदाबाद से विधायक चुने गए थे। उनकी स्वाभिमानी एवं जुझारू ज़िन्दगी की अनेक घटनाएं विलक्षण हैं। वह अपने संकल्पों के लिए कितने समर्पित थे, इस बात का अनुमान उनके जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं से लगाया जा सकता है। उनके व्यक्तित्व की एक विलक्षण बात यह भी थी कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करने के लिए पूरी जुझारू जिन्दगी काले वस्त्र पहने। लाला लाजपत राय ने उन्हें अपने अखबार वन्दे मातरम का प्रकाशक एवं महाप्रबंधक बनाया था। अक्तूबर 1899 में लाहौर में जन्मे इस विलक्षण स्वाधीनता सेनानी ने 25 फरवरी 1963 को दिल्ली में अंतिम सांस ली थी। लाला केदारनाथ भी शहीदे आजम भगत सिंह के साथियों में शुमार थे। वह उन दिनों शहीदे आजम द्वारा स्थापित नौजवान भारत सभा की पहली पंक्ति में थे। यह सभा 12 अप्रैल, 1928 को गठित की गई थी। इसकी गतिविधियां लाहौर व मेरठ से संचालित होती थीं। उन्हीं दिनों 'लाहौर-षड्यंत्र केस' के साथ-साथ 'मेरठ षड्यंत्र केस' भी ब्रिटिश हुकूमत ने गढ़ा था। 'गढ़ा' शब्द का प्रयोग सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसे मामलों में गवाह भी झूठे होते थे और पूरा इस्तगासा भी झूठ पर आधारित होता था।

सम्पादकीय...

सब हवा ही हवा

कह रहे हैं कि जो आदम कद से बड़ा आकार दिखाई दे रहा है, उसमें कोई तत्व ही नहीं है। सिर्फ पतली सी रबर की थैली है। चूंकि थैली रबर की है, इसलिए उसे फुलाकर काफी बड़ा किया जा सकता है। इसी से बड़ा सा आकार दिखाई देता है। वर्ना सब हवा ही हवा है, जिसने रबर की थैली को इतना फुलाया हुआ है कि लोगों को विशालकाय होने का भ्रम होता है। और तो और बहुत से लोग आकार की विशालता के भ्रम में उसने भी लगे हैं। उन्हें लगता है कि जब आकार इतना बड़ा है, तो ताकत कितनी ज्यादा होगी? जबकि सच्चाई यह है कि सिर्फ एक पिन चुभोने की जरूरत है, तेजी से सारी हवा निकल जाएगी और देखते ही देखते महाकाय तस्वीर, फुस्स हो जाएगी। लेकिन, ये सब तो विपक्ष वालों की बातें हैं, बातों का क्या? दरअस्ल, विपक्ष वालों के अपने दावे में ही अंतर्विरोध है। एक तरफ कह रहे हैं कि फूला हुआ गुब्बारा है, आसानी से हवा निकाली जा सकती है। एक पिन चाहिए और एक पिन चुभोने वाला चाहिए, बस। और दूसरी ओर खुद ही कह रहे हैं कि गुब्बारा गर्म हवा से भरा हुआ है। अब अगर गुब्बारा गर्म हवा से भरा है, तो जमीन पर तो टिका हुआ होगा नहीं। गर्म हवा का गुब्बारा है, तो जरूर जमीन से ऊपर उठा हुआ होगा। सिर्फ उठा हुआ क्यों, बाकायदा हवा में तैर रहा होगा। विज्ञान यही कहता है! अब जो गुब्बारा जमीन से ऊपर, हवा में तैर रहा है, उसमें क्या कोई ऐसे ही पिन चुभो सकता है? पिन क्या मिसाइल है, जो उड़कर जाएगी और जाकर गुब्बारे में चुभ जाएगी? और वह भी तब जबकि गुब्बारा सिर्फ हवा में एक जगह रुका हुआ नहीं है, बाकायदा हवा में तैर रहा है। अब मोदी जी पर किसी रस्सी-वस्सी से बंधा गुब्बारा होने का इल्जाम तो विपक्ष वाले भी नहीं लगा सकते हैं। किसी रस्सी-वस्सी से बंधे होते तो क्या यह मुमकिन था कि इधर संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, और उधर मोदी जी उड़कर इंग्लैंड और मालदीव की चार दिन की यात्रा पर निकल गए! और यह कोई पहली बार भी नहीं हुआ है। उल्टे अब तो यही नया नार्मल है यानी इधर संसद में हंगामा चालू और उधर मोदी जी के हवाई जहाज का इंजन चालू। और हां, हवाई जहाज के इंजन के चालू होने से याद आयी। पार्लियामेंट में बताया गया है कि 2021 से लगाकर अब तक, पांच साल में मोदी जी की विदेश यात्राओं पर कुल 350 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं यानी 70 करोड़ रुपये सालाना। सवाल यह है कि अगर मोदी जी वाकई गरम हवा का गुब्बारा होते, तो क्या इतना खर्चा करने की जरूरत पड़ती? नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि यह खर्चा अपने आप में बहुत ज्यादा है? सीधी सी बात है कि अगर विश्वगुरु बनने की इच्छा पाली है या भक्तों की भाषा में कहें तो शेर पाला है, तो खर्चा तो लगेगा ही। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं आता है, फिर विश्वगुरु के आसन की दावेदारी मुफ्त कैसे आ जाएगी। अब प्लीज ये मत कहने लगना कि विश्व गुरु का आसन मिला ही कहां है? आसन मिलने के खर्चे की नहीं, आसान की दावेदारी के यानी उम्मीदवारी के और उसके लिए प्रचार के खर्चे की बात की जा रही है। बेशक, इसमें विदेश में हर जगह, ''मोदी-मोदी'' करने के लिए, देश-विदेश से निवासी-अनिवासी भारतीयों को जुटाने का खर्चा भी शामिल है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि अगर मोदी जी गर्म गैस का गुब्बारा होते, तो कम से कम हवाई जहाज से लेकर तेल तक यानी हवाई यात्रा का खर्चा तो बच ही गया होता। बस गुब्बारे को दिशा देने की जरूरत होती। और हां! थोड़ा समय ज्यादा लग सकता था, पर उसमें क्या हर्ज था, उल्टे तब तक संसद का सत्र भी निपट गया होता। न मोदी जी रहते और न उन्हें किसी सवाल का जवाब देना पड़ता। सवालों के जवाब से ध्यान आया, मोदी जी को गर्म हवा का गुब्बारा बताने वाले तो बिल्कुल ही गलत हैं। कहां छप्पन इंच की छाती वाले मोदी जी और कहां हवा भरा गुब्बारा। गुब्बारे में तो पेट ही पेट होता है, छाती तो होती ही नहीं है। और ''ऑपरेशन सिंदूर'' की जबर्दस्त सफलता के बाद, मोदी जी की छिवी पर सवाल उठाने वाले भी, उनकी छाती के साइज पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भी कोई मामूली सफलता नहीं है। मामूली सफलता तो वो होती है, जिसका एलान ऑपरेशन के खत्म होने के बाद किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर तो जैसाकि मोदी जी ने कहा, सेनाध्यक्ष ने भी कहा, औरों ने भी कहा, अब भी जारी है! ऑपरेशन जारी है, पर सफलता हो भी चुकी, ऐसा चमत्कार छप्पन इंच के बिना क्या संभव है? रही बात लड़ाई रुकवाने के ट्रम्प के दावे की तो उसका मोदी जी ने जोरदार तरीके से खंडन तो उसी दिन कर दिया था, जब उन्होंने एलान किया था कि लड़ाई रुकी नहीं है, उसमें सिर्फ पॉज हुआ है! जब लड़ाई रुकी ही नहीं है, फिर ट्रम्प जी के लड़ाई रुकवाने के दावे का मतलब ही क्या है? ऐसे दावों का मोदी जी क्यों खंडन करने जाएं। सो ट्रम्प जी के पच्चीसवीं बार के दावे पर भी मोदी का वही जवाब है- लड़ाई तो रुकी ही नहीं है, सिर्फ पॉज हुई है, बाकी नो कमेंट जी! अब ये तो गर्म हवा वाले गुब्बारे के लक्षण नहीं हैं। और गर्म हवा के गुब्बारे का लक्षण तो यह भी नहीं है कि धनखड़ साहब, तीन घंटे में ही उपराष्ट्रपति हैं से थे हो गए। नया रिकार्ड भी बना दिया, कार्यकाल के बीच में उपराष्ट्रपति की विदाई का। और वह भी मोदी जी के एक इशारा तक किए बिना। मोदी जी ने इशारा किया भी तो तब, जब धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा दे दिया। मोदी जी ने भी उनके स्वास्थ्य की कुशलता की कामना कर दी। पीछे से भाई लोगों ने धनखड़ की विदाई पार्टी का खर्चा भी बचा लिया। ऐसे बड़े-बड़े फैसले लेने वाले पीएम को विरोधी भी गर्म हवा का गुब्बारा कैसे कह सकते हैं? यह तो राष्ट्र विरोधी हरकत है। कोई गर्म हवा का गुब्बारा न कहे मेरे पीएम को!

क्या ट्रंप का भारत-चीन से श्रम हायरिंग प्रतिबंध का आदेश, भारत- ब्रिटेन एफटीए का जवाब है ? एक तथ्यात्मक विश्लेषण

वैश्विक स्तरपर भारतीय बौद्धिक क्षमता व टैलेंट के बारे में सदियों से दुनियाँ का हर देश जानता है। आज दुनियाँ के अनेक देश भारत के साथ एफटीए की आस लगाए बैठे है, भारत राष्ट्रीय हित में डील जरूर करेगा,जैसे ब्रिटेन के साथ की है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र मानता हूं कि अब भारत की बढ़ती ताकत से प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष,स्वास्थ्य,शिक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों के विशेषज्ञ व विकसित देश संज्ञान लेकर अपनी रणनीतियां बना रहे है, लेकिन साँच को आँच नहीं भारत अपने ही देश में स्वदेशी टेक कंपनियां को सेवाएं देकर, नामी टेक कंपनियों से आगे निकलने का हौसला रखकर, मंजिल तक पहुंचने में, जज्बा और जांबाजों से पूरी ताकत लगा देगा। आज 26 जुलाई 2025 को भारत के पीएम मालदीव की राजकीय यात्रा से लौटे जहां वे स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि थे, कुछ दिन पहले जो मालदीव भारत आउट के नारों से गूंज रहा था वह आज भारत इन के नारों से सराबोर हो रहा है जिसे देखकर दुनियाँ हैरान है। यह चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन-भारत का एग्रीमेंट 24 जुलाई 2025 को हुआ था व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में 24,-25 जुलाई 2025 को ही एआई सम्मिट में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एप्पल, मेटा जैसी अनेक टेक कंपनियों से कहा कि वे अमेरिकी फर्स्ट को साकार करने के लिए, भारत से श्रमिक हायरिंग करना बंद कर अमेरिकीयों को प्राथमिकता दें।ट्रंप की हालिया घोषणा (24-25 जुलाई 2025 को एआई सम्मिट में) के अनुसार, उन्होंने अमेरिकी टेक कंपनियों जैसे गूगल,माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा आदि से कहा है कि वे भारत से हायरिंग बंद करें औरअमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा- अमेरिकी कंपनियाँ भारत जैसी जगहों से इंजीनियर और तकनीशियन हायर कर रही हैंयह उनकी ग्लोबलिस्ट माइंडसेट के कारण हो रहा है, जिसे अब खत्म होना चाहिए।उन्होंने तीन एआई -फोकस्ड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जारी किए- एआई -इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बनाने की रणनीति, फेडरली फंडेड एआई को पोलिटिकल न्यूट्रलिटी का पालन करना, और अमेरिकी एआई एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना।अब मुद्दा यह उठा है कि क्या ट्रंप ने उसी दिन यह बयान भारत-ब्रिटेन एफटीए का जवाब है? मेरा मानना है कि नहीं, यह भले ही एक ही दिन निर्णय हुए हो परंतु नीचे पैराग्राफ में हम तथ्यात्मक विश्लेषण से इसका जवाब देंगे।चूंकि ब्रिटेन का, यूरोपीय यूनियन से त्यागपत्र देकर तुरंत भारत से एफटीए करना, भारतीय विदेशमंत्री की चीनी राष्ट्रपति व विदेशमंत्री समकक्ष से मिलना व ट्रंप का भारत-चीन श्रम हायरिंग प्रतिबंध आदेश का संज्ञान कुछ दूसरे एंगल से लिया जा रहा है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, क्या ट्रंप का भारत- चीन से श्रम हायरिंग प्रतिबंध का आदेश,भारत-ब्रिटेन एफटीए का जवाब है ? एक तथ्यात्मक विश्लेषण। साथियों बात अगर हम ट्रंप द्वारा 24-25 जुलाई 2025 को वॉशिंगटन डीसी में एआई सम्मिट में हायरिंग प्रतिबंध की घोषणा का भारत-ब्रिटेन एफटीए समझौते से कोई संबंध नहीं होने की करें तो ट्रंप ने कल वॉशिंगटन डीसी में आयोजित एआई समिट में कहा अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां हमारी आजादी का लाभ उठाती हैं, लेकिन फैक्ट्रियां चीन में लगाती हैं और भारत से लोग भर्ती करती हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अमेरिकी वर्कर्स को प्राथमिकता दें, यही देश हित में है। ट्रम्प ने टेक कंपनियों के ग्लोबलिस्ट माइंडसेट की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिकियों को सबसे पहले नौकरी मिलनी चाहिए। ट्रंप के मुताबिक विदेशों में फैक्ट्री और कर्मचारियों पर पैसा लगाकर कंपनियां अमेरिकी टैलेंट के हक को मार रही हैं।उन्होंने तीन एआई - फोकस्ड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जारी किए-(1) एआई -इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बनाने की रणनीति, (2) फेडरेली फंडेड एआई को पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का पालन करना, और (3) अमेरिकी एआई एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा।अब सवाल उठता है कि क्या यह भारत-ब्रिटेन एफटीए (मुफ्त व्यापार समझौता) के जवाब में लिया गया कदम है? मेरा मानना है नहीं, ट्रंप की घोषणा और एआई सम्मिट में की गई घोषणाएँ संयुक्त राज्य अमेरिका के घरेलू रोजगार व तकनीक राजनैतिक एजेंडे के अनुरूप है। इनका भारत-ब्रिटेन एफटीए (जो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 24 जुलाई 2025 को हुआ) से कोई सम्बंध नहीं है। ट्रंप का जोर अमेरिकी टेक उद्योग को भारत से दूरी बनाने पर है, ताकि अमेरिकी श्रमिकों को अवसर मिले। इसलिए, ट्रंप के आदेश को एफटीए का जवाब कहना तथ्यात्मक सही नहीं है। साथियों बात अगर हम भारत ब्रिटेन एफटीए के तथ्यों की करें तो,ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन को नए व्यापार साझेदारों की तलाश थी। भारत, एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति और उपभोक्ता बाजार के रूप में, ब्रिटेन के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। कई वर्षों के वार्ता के बाद, जुलाई 2025 में भारत और ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, निवेश,आईपी और श्रमिक गतिशीलता को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधानों से युक्त था। 90 पर्सेंट उत्पादों पर टैरिफ समाप्त-ब्रिटेन को भारतीय निवेशकों के लिए वीजा प्रक्रियाएँ आसान बनाना, डेटा संरक्षण और तकनीकी सहयोग पर विशेष अनुच्छेदिका, स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहन यह समझौता भारत के लिए यूरोप के बाहर ब्रिटेन के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक करार बन गया। साथियों बात अगर हम ट्रंप द्वारा 24-25 जुलाई 2025 को एआई सम्मिट में हायरिंग प्रतिबंध आदेश के दिए वक्तव्य की करें तो, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में एक बयान देकर टेक जगत में हलचल मचा दी है, उन्होंने अमेरिका की दिग्गज कंपनियों-गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा जैसी फांग कंपनियों से कहा कि वे भारत में लोगों को नौकरी देना बंद करें और केवल अमेरिकियों को प्राथमिकता दें।उनका यह बयान वायरल हो गया, जिसमें वे इन कंपनियों को ग्लोबलिस्ट माइंडसेट का आरोप लगाते नजर आए। ट्रंप ने कहा कि हमारी टेक कंपनियों ने अमेरिका की आजादी का फायदा उठाकर अपने ऑफिस चीन में खोले, भारत में कर्मचारियों की भर्ती की और मुनाफा आयरलैंड में जमा किया,अब ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कंपनियां ट्रंप की बात मानेंगी? और क्या भारत में हजारों इंजीनियरों की नौकरी खतरे में है? ट्रंप ने टेक कंपनियों से भारत में हायरिंग रोकने की अपील की,टेक कंपनियां भारत में टेक टैलेंट और कम लागत का फायदा उठाना जारी रखेंगी ! साथियों बात अगर एफटीए व हायरिंग प्रतिबंध के तथ्यात्मक विश्लेषण की करेंगे,भारत-ब्रिटेन एफटीए से प्रेरित नहीं, बल्कि अमेरिका की आंतरिक राजनीति और रिपब्लिकन वोट बैंक के गणित पर आधारित है।(1) भारत और चीन का विशेष उल्लेख क्यों?भारत और चीन अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में आउटसोर्सिंग के प्रमुख स्रोत रहे हैं। टीसीएस,इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो जैसी कंपनियाँ गूगल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों को बौद्धिक सेवाएं देती रही हैं।ट्रंप का यह संदेश न केवल चीन जैसे प्रतिद्वंद्वी को लक्षित करता है, बल्कि भारत जैसे भागीदार देश की भूमिका को भी सीमित करने की कोशिश करता है (2) अमेरिका की घरेलू राजनीति बनाम वैश्विक कूटनीति (अ) ट्रंप का घरेलू एजेंडा -2024 चुनाव में ट्रंप की हार और 2025 में वापसी की तैयारी ने उन्हें पुनः -अमेरिका फर्स्ट-एजेंडे की ओर ले गया है।उन्होंने पहले भी 2016–2020 के कार्यकाल में एच -1बी वीजा और आउट सोर्सिंग पर कठोर नीति अपनाई थी।यह घोषणा अमेरिकी मध्यम वर्ग,ब्लू कॉलर वोटर्स और बेरोजगार युवाओं को साधने का प्रयास है। (3) वैश्विक समझौतों पर ट्रंप का दृष्टिकोण-ट्रंप वैश्विक व्यापार समझौतों के आलोचक रहे हैं, जैसे एनएएफटीए, टीपीपी आदि।वह बहुपक्षीय गठबंधनों को अमेरिका के लिए हानिकारक मानते हैं और एकतरफा लाभ की नीतियाँ पसंद करते हैं।इसलिए यह समझना जरूरी है कि ट्रंप की घोषणा भारत-ब्रिटेन एफटीए से प्रेरित नहीं, बल्कि अमेरिका की आंतरिक राजनीति और रिपब्लिकन वोट बैंक के गणित पर आधारित है। (4) क्या यह भारत-ब्रिटेन एफटीए का जवाब हो सकता है?- भारत- ब्रिटेन एफटीए का अमेरिका से सीधा संबंध नहीं।यह द्विपक्षीय समझौता है, जो यूरोपीय संघ या अमेरिका को प्रभावित नहीं करता।एफटीए के दायरे में अमेरिकी टेक कंपनियाँ या अमेरिकी श्रमिक नहीं आते। (5) भारत-ब्रिटेन साझेदारी से अमेरिका को कोई रणनीतिक खतरा नहीं अमेरिका और भारत स्वयं भी रणनीतिक साझेदार हैं -क्वाड, आईपीईएफ,2+2 वार्ता आदि मंचों पर।भारत-ब्रिटेन एफटीए से अमेरिका की जीडीपी या टेक सेक्टर पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता। (6) अमेरिका की कंपनियाँ भारत को आउट सोर्सिंग केंद्र मानती है, एआई और आईटी सेक्टर में भारत की प्रतिभा का उपयोग अमेरिका की उत्पादकता को बढ़ाता है।इसपर प्रतिबंध अमेरिका के लिए भी घाटे का सौदा हो सकता है। इस प्रकार ट्रंप का यह कदम भारत- ब्रिटेन एफटीए का उत्तर नहीं, बल्कि स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता (अमेरिकन औतारकय) की सोच का हिस्सा है।भारत सरकार ने अब तक इस पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी है, जो इंगित करता है कि भारत इसे अमेरिका की आंतरिक राजनीति मानता है, न कि एफटीए के खिलाफ कूटनीतिक कदम।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कदम ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पंचशाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/570, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/36862)

धर्म परिवर्तन कराकर युवती के साथ दुष्कर्म का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

कुशीनगर ।

हिन्दू युवती को भगाकर धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को थाना रामकोला की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि दिनांक 26.07.2025 को थाना रामकोला पर पीडिता के पिता द्वारा सूचना दिया गया कि उनकी पुत्री को इसराफिल अंसारी पुत्र इद्रीश अंसारी निवासी रामपुर भाठ थाना रामकोला जनपद कुशीनगर ने धर्म परिवर्तन कराकर भगा ले गया है। सूचना पर थाना रामकोला पर मु0अ0सं0 324/ 2025 पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा द्वारा पीड़िता की सकुशल बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। जिसके क्रम में सोमवार को थाना रामकोला की पुलिस टीम द्वारा पीडिता की सकुशल बरामदगी करते हुए अभियुक्त इसराफिल अंसारी पुत्र इद्रीश अंसारी निवासी रामपुर भाठ थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से पुलिस द्वारा पूछ-ताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इसराफिल, जो पहले से शादीशुदा है,ने पीडिता को प्रलोभन देते हुए अपने प्रेम जाल में फसाकर शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा तथा उसे लेकर अपने साथ भागने के फिराक में था। विरोध करने पर उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी देकर डरा धमका कर रखता था। गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में अपराध निरीक्षक संतोष कुमार श्रीवास्तव, उ0नि0 शिवम द्विवेदी, म0उ0नि0 करिश्मा यादव,का0 जितेन्द्र यादव, म0 का0 प्रियंका यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर शामिल रहे।

पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गई सड़क के मरम्मत कार्य का होगा सत्यापन : डीएम

जल जीवन मिशन अंतर्गत संचालित योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक सभी सुधरे कार्यों को गुणवत्तायुक्त ससमय पूर्ण करने हेतु दिए गए निर्देश

कुशीनगर।

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार आहूत की गयी। बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता उप्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज 3 में कुल 453 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिनसे जनपद के कुल 687 ग्राम पंचायतो के 904 राजस्व ग्रामों में कुल 334718 गृह जल संयोजन किया जाना है जिसके सापेक्ष 84 अदद ग्राम पंचायत पेयजल योजनाओं का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। समीक्षा बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता उप्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि उपरोक्त 453 योजनाओं में से 103 योजनाए विद्युत आधारित है जिनमें से अबतक मात्र 20 योजनाओं पर ही विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके कम में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि उनके स्तर से विद्युत विभाग से सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को उक्त कार्यों को अतिशिघ्र पूर्ण कराने हेतु पत्र प्रेषित किया जाय। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में कुल 6448 किमी0 वितरण प्रणाली बिछाना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष अब तक कुल 6252 किमी0 वितरण प्रणाली बिछायी गयी है, तथा शेष 196 किमी0 वितरण प्रणाली विभिन्न कारणों यथा लोक निमार्ण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र न प्राप्त होना या अन्य छोटे-बड़े विवाद के कारण शेष है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला प्रशासन के सहयोग से समन्वय स्थापित करते हुये शेष कार्यों को यथा शीघ्र पूर्ण करा लिया जाय। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा जनपद में चल रहे समस्त कार्यों को निर्धारित समयावधि में तथा निर्धारित मानक के अनुरूप कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये तथा साथ ही उपरोक्त कराये जा रहे कार्यों का सत्यापन टीम गठित कर करा लिया जाने का निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, जू 0ई0, कार्यदायी एजेंसी मे0 एन0सी0सी0लिमिटेड के प्रतिनिधि, डी0पी0एम0यू0 व टी 0 पी0आई0ए0 के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

वनटांगिया को अलग ग्राम पंचायत बनाने की मांग

महराजगंज।

जनपद के 18 वनटांगिया ग्रामों को अलग ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सोमवार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने वनटांगिया गांवों के समुचित विकास के लिए परिसीमन की आवश्यकता पर बल दिया। ज्ञापन में बताया गया कि वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 और संबद्ध नियमावली 2008 के तहत वनटांगिया गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त है। साथ ही, पंचायत चुनाव में मतदान का अधिकार भी मिला है। गांव के मनोज निषाद ने बताया की गांवों को अन्य राजस्व ग्रामों के साथ जोड़े जाने के कारण ग्राम प्रधान बाहरी व्यक्ति होता है, जिससे वनटांगिया गांवों का विकास अवरुद्ध हो रहा है। गांवों की जनसंख्या पंचायत चुनाव के मानक को पूरा करती है, फिर भी इन्हें स्वतंत्र ग्राम पंचायत का दर्जा नहीं मिला है। इस दौरान विजय साहनी, घनश्याम, प्रदीप, अनिल उपस्थित रहे।

पंचमुखी धाम इटहिया में उमड़े श्रद्धालु

विशाल भंडारे का हुआ आयोजन, विधायक समेत कई गणमान्य लोग हुए शामिल

नेबुआ नौरंगिया कुशीनगर ।

कुशीनगर के तहसील खड्डा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मदनपुर सकरौली में स्थित नहर पर शिव मंदिर पर श्रावणी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सावन के तीसरे सोमवार को प्रसिद्ध पंचमुखी धाम शिव मंदिर इटहिया में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।मदनपुर सुकरौली के शिव मंदिर के साधु श्रीकांत उर्फ झमेला साधु ने बताया कि इस आयोजन में खड्डा विधायक विवेकानंद पाण्डेय, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि दुर्गेश्वर वर्मा, प्रिंस मद्धेशिया, समाजसेवी जितेंद्र यादव, कल सिंह, भूपत यादव, जितेंद्र कुमार यादव, मंजेश साहनी, अजय भारती, दिलीप मिश्रा, संदेश भारती, गुलाब मुसहर, गुड्डू गुप्ता, धर्मेंद्र यादव, वीरेंद्र यादव और अभिषेक सिंह सहित कई लोगों का सहयोग रहा।साधु श्रीकांत ने बताया कि सावन के प्रत्येक दिन पंचमुखी शिव धाम जाने वाले श्रद्धालु भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं। भक्तों ने विधि-विधान से मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का पूजन किया। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक के साथ बेलपत्र और पुष्प भी अर्पित किए। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल-बम के जयकारों से गूंजता रहा।

श्रद्धालुओं ने बताया कि सावन मास के सोमवार को विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा-अर्चना का विशेष विधान है। श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था के साथ पूजन कार्य संपन्न किया।

रिश्तेदारी से लौट रहे व्यक्ति की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत

भटनी देवरिया ।

भटनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भटनी-बनकटाशिव मार्ग पर ग्राम परसौनी पुल के पास सोमवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 48 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की पहचान ग्राम पुरनाछपर निवासी बैजनाथ यादव पुत्र रामबहादुर के रूप में हुई है।

बताया जा रहा है कि बैजनाथ यादव किसी रिश्तेदारी से लौटकर घर आ रहे थे, तभी गांव से लगभग एक किलोमीटर पहले परसौनी पुल के पास उन्हें एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वे सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों द्वारा तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।घटना की सूचना पर भटनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल देवरिया भेज दिया। मृतक अपने पीछे पत्नी, चार पुत्रियाँ और एक पुत्र अवनीश को छोड़ गए हैं। परिवार में दो बेटियों की शादी हो चुकी है। जैसे ही यह दुखद समाचार घर पहुंचा, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी व बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने इस हादसे के लिए अज्ञात वाहन को जिम्मेदार ठहराते हुए थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

परसौनी पुल के पास हुआ दर्दनाक हादसा, परिवार में मचा कोहराम

गीको रोमन स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में प्रतीक पाण्डेय को गोल्ड व संजय कुमार राय को मिला सिल्वर मेडल

गोरखपुर।

महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में डाक विभाग के कुल 12 राज्यों से पहलवानों ने हिस्सा लिया। गोरखपुर रीजन का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतीक पाण्डेय ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में ग्रीको रोमन कुश्ती में अपने प्रतिद्वंदी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया । वहीं संजय कुमार राय ने 67 किलोग्राम भार वर्ग में अपने प्रतिद्वंदी को हराकर रजत पदक अपने नाम किया। बताते चलें कि प्रतीक पाण्डेय मूलतः साख डांड, खजनी के रहने वाले हैं और रामजानकी नगर बशारतपुर में अपने परिवार के साथ रहते हैं । इस प्रतियोगिता में इन्होंने लगातार आठवीं बार गोल्ड मेडल जीता है। वहीं संजय कुमार राय के बारे में बात करें संजय कुमार राय मूलतः गौरी बाजार देवरिया के रहने वाले हैं, जो अरण्य बिहार कॉलोनी खोराबार में सपरिवार रहते हैं, इन्होंने लगातार पंद्रह बार गोल्ड मेडल जीता है, किंतु इस बार इन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन से गोरखपुर मण्डल के डाक विभाग के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई।

दोनों पहलवानों ने कुश्ती में गोरखपुर क्षेत्र का दबदबा कायम रखते हुए अपने प्रदर्शन से क्षेत्र का नाम रोशन किया है । दोनों खिलाड़ियों के गोरखपुर पहुंचते ही पोस्टमास्टर जनरल गोरखपुर क्षेत्र गौरव कुमार श्रीवास्तव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दोनों पहलवानों का स्वागत किया और वहां उपस्थित समस्त स्टाफ एवं कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने भी उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाई दी।

महात्मा बुद्ध कृषि एंव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की हुई समीक्षा

कुशीनगर।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के प्रमुख सचिव रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कार्यालय में निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। निर्माण कार्यों का कार्यदाई संस्था से अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने उपरांत उन्होंने निर्धारित समय में निर्माण कार्य गुणवत्ता व मानक के साथ पूरा करने के लिए सख्त हिदायत दी। बैठक में वि0वि0 के नोडल और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के कुलपति डा. बिजेंद्र सिंह व डीएम महेंद्र सिंह तंवर सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

प्रमुख सचिव ने बताया कि विवि निर्माण के लिए दो किस्तों में धन आवंटन हो चुका है। तीसरी किस्त कार्यों के मूल्यांकन के बाद किया जाएगा। विवि निर्माण के बीच बीच में पड़ने वाले किसानों की भूमि को अधिग्रहित करने के लिए राजस्व विभाग को निर्देश दिया है। किसानों को इसके बदले मुआवजा दिया जाएगा। जबकि प्रभावित किसानो को जमीन के बदले जमीन ही चाहिए। सचिव ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय को हस्तांतरित होने वाली 145 एकड़ से अधिक भूमि अब भी संस्कृति विभाग की है। उसका विवि को हस्तांतरण शासन स्तर से हो जाएगा। कार्यदाई एजेंसी को विवि निर्माण व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नोटिस को लेकर नाराजगी जताई। कहा कि विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का काम पूरा होना चाहिए।

ताकि निर्माण में कोई अड़चन न आए। सचिव ने निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय के मानचित्र का भी अवलोकन किया। प्रत्येक बिंदु की जानकारी हासिल की। इसके पूर्व होटल पथिक निवास पहुंचने पर उन्हें बुके व बुद्ध प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी लेने के क्रम में कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि योजनाओं की भी जानकारी हासिल किया। इसमें यूरिया खाद की समितियों पर किल्लत का मुद्दा प्रमुख था।

इसके अलावा किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड सहित तमाम योजनाओं व उनके लाभान्वित होने वाले पात्रों की मौजूदा स्थिति से रू-ब-रू हुए। सचिव ने कुछ बिंदुओं पर खामी पाए जाने पर जिला कृषि अधिकारी को फटकार भी लगाई। उन्हें योजनाओं के क्रियान्वयन कार्य में गंभीरता व सक्रिय होकर पूरा करने के लिए निर्देशित किया। हालांकि सचिव ने यूरिया खाद की किल्लत दूर होने की बात कही। जहां नहीं होगा, वहां भी मिल जाएगा। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर द्वारा प्रमुख सचिव द्वारा दिए गए निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन किए जाने का आश्वासन देते हुए आश्वस्त किया गया गया कि सभी कार्य शासन की मंशा अनुरूप ससमय पूर्ण कर लिए जाएंगे। इस मौके पर एडीएम वैभव मिश्रा, एसडीएम आशुतोष कुमार, तहसीलदार धर्मवीर सिंह,उप कृषि निदेशक अतीन्द्र सिंह,संयुक्त निदेशक शहरी एवं आवासीय गिरीश चंद्र सिंह ,जिला कृषि अधिकारी डॉ.मेनका, पर्यटन सूचना अधिकारी डा. प्राण रंजन,संस्कृति विभाग से तेज प्रताप शुक्ला,कार्यदाई संस्था के अधिकारी, राजस्व निरीक्षक ब्रजेश मणि सहित अन्य सभी संबंधित गण मौजूद रहे।

जिला प्रशासन किसानों को देगा मुआवजा अधिग्रहण की जाएगी भूमि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का निर्देश संस्कृति विभाग की जमीन का हस्तान्तरण कृषि विश्वविद्यालय के नाम, शासन स्तर का मामला उक्त निर्माण कार्य सहित अन्य को समय से पूरा करने का दिएनिर्देश मूल्यांकन बाद तीसरी किस्त की जाएगी अवमुक्त कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी कर दिए आवश्यक निर्देश

टेरी की रिपोर्ट में खुलासाः दिल्ली-एनसीआर में छाया प्लास्टिक का अदृश्य खतरा, यमुना और अन्य जल स्रोत भी जहरीले

नई दिल्ली। भारत की राजधानी और उसके आसपास का क्षेत्र अब केवल वायु प्रदूषण या जल संकट से ही नहीं बल्कि सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण संकट से भी जूझ रहा है। जुलाई 2025 में जारी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) की नवीनतम शोध रिपोर्ट एन्वायरनमेंटल पर्सिस्टेंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स इन अर्बन इकोसिस्टम्स में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की हवा, जल और मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक की सांद्रता विश्व स्वास्थ्य मानकों से काफी अधिक पाई गई है। शोध टेरी ने नीति आयोग और जर्मन सहयोगी संस्था जीआईजेड के साथ किया है। शोधकर्ताओं ने दिल्ली-एनसीआर के 12 प्रमुख शहरी व अर्ध-शहरी क्षेत्रों से हवा, पानी व मिट्टी के नमूने एकत्र किए और उन्हें एफटीआईआर व रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीकों से जांचा। रिपोर्ट में पाया गया कि दिल्ली की हवा में प्रति घनमीटर 1.6 से 4.2 माइक्रोप्लास्टिक फाइबर मौजूद हैं। राजधानी से गुजर रही यमुना और प्रदेश के अन्य जल स्रोतों में प्लास्टिक की सांद्रता डब्ल्यूएचओ सीमा से छह गुना अधिक है। टायर घर्षण, सिंथेटिक कपड़ों से निकले रेशे, निर्माण कार्य व प्लास्टिक कचरा। ये सूक्ष्म कण हवा, पानी और खाद्य पदार्थों के जरिये शरीर में पहुंचकर विषैले प्रभाव डाल सकते हैं। मिट्टी में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक्स सूक्ष्मजीवों को प्रभावित कर कृषि उत्पादन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स अब समुद्री जीवन तक सीमित नहीं हैं। यह हमारे फेफड़ों, भोजन और मस्तिष्क तक पहुंच चुके हैं। यह मौन आपदा हमारे भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती है। यह स्थिति स्वास्थ्य आपातकाल की तरह है, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रति घनमीटर हवा में माइक्रोप्लास्टिक फाइबर का स्तर यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी (ईईए) की ओर से निर्धारित 0.8 फाइबर प्रति घनमीटर की औसत सुरक्षित सीमा से दोगुने से भी अधिक है। यमुना और अन्य जलस्रोतों में प्रति लीटर पानी में औसतन 8.5 से 12 माइक्रोप्लास्टिक कण मिले। यह डब्ल्यूएचओ के 2-3 कण/लीटर के अस्थायी सुरक्षित मानक से चार गुना अधिक है। लंदन (थेम्स नदी) में प्रति लीटर पानी में औसतन 4.4 जबकि लॉस एंजेलेस की नदियों प्रति लीटर में औसतन 5.1 माइक्रोप्लास्टिक कण पाए गए। भारत में मिट्टी के 100 ग्राम नमूनों में 350 से अधिक प्लास्टिक फाइबर पाए गए, जो भूमि की जैविक गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट में उल्लेख है कि हवा में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक्स का औसत आकार पांच माइक्रोन से कम था, जो मानव श्वसन तंत्र में पहुंचने की क्षमता रखते हैं। टेरी की रिपोर्ट बताती है कि भारत को सिर्फ वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ही नहीं, बल्कि माइक्रोप्लास्टिक सूचकांक को भी भविष्य की नगर नियोजन, स्वास्थ्य और पर्यावरण नीति में शामिल करना चाहिए। ईयू, यूएसए और चीन ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। भारत में गंभीर हस्तक्षेप जरूरी है। टेरी की रिपोर्ट ने सरकार और नीति निर्माताओं के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इनमें सबसे पहले राष्ट्रीय माइक्रोप्लास्टिक निगरानी नेटवर्क (नेशनल माइक्रोप्लास्टिक मॉनिटरिंग नेटवर्क) की स्थापना का सुझाव दिया गया है।सिंथेटिक वस्त्रों पर कर और पर्यावरण लेबलिंग प्रणाली, प्लास्टिक आधारित टायरों पर नियमन और निर्माण गतिविधियों में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने जैसी सिफारिशें शामिल है।

लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस

लोकसभा में गरजे राजनाथ सिंह - ऑपरेशन सिंदूर बस रुका है, पाकिस्तान ने छेड़ा तो फिर होगा

नई दिल्ली।

संसद में दोपहर दो बजे फिर से मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के साथ शुरू हुई। इस चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ कहा कि भारत ने यह सैन्य कार्रवाई किसी के दबाव में आकर नहीं रोकी, बल्कि अपने सभी तय लक्ष्यों को हासिल करने के बाद ही इसे विराम दिया गया था। राजनाथ सिंह के इस बयान से पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर कड़ा संदेश गया है। राजनाथ सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने का मुख्य मकसद पाकिस्तान में वर्षों से पल रहे आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से खत्म करना था। भारतीय सेनाओं ने सिर्फ उन्हीं जगहों और लोगों को निशाना बनाया जो आतंकियों को लगातार मदद दे रहे थे और भारत पर हमला करने में शामिल थे। उनका यह भी कहना था कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ना बिल्कुल नहीं था, बल्कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना था। राजनाथ सिंह के मुताबिक 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स पर जबरदस्त हमला किया, तब पाकिस्तान ने अपनी हार मान ली। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई। राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान ने हमारे डीजीएमओ से बात की और कहा कि महाराज अब रोकिए। भारत ने इस अपील को इस शर्त पर स्वीकार किया कि यह ऑपरेशन केवल अस्थायी रूप से रोका गया है। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी गतिविधि होती है, तो यह ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को यह हार केवल एक सामान्य विफलता नहीं थी, बल्कि यह उसके सैन्य बल और मनोबल, दोनों की करारी हार थी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बातचीत कर कार्रवाई रोकने की अपील की थी और दोनों देशों के बीच संवाद के बाद ही भारत ने इसे रोकने का फैसला लिया। राजनाथ सिंह ने गर्व से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के अदम्य शौर्य और पराक्रम को 140 करोड़ भारतीयों ने देखा।

भारतीय जेट तबाह होने पर राजनाथ बोले- परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत; कितनी पेंसिल टूटीं या पेन गुमे, यह बेमानी

देशवासी ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन तंदूर चाहते थे- सपा सांसद

सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा- 100 आतंकियों को मारा, लेकिन इनमें वो चार आतंकी शामिल थे या नहीं। ये सरकार ने नहीं बताया। पहलगाम हमले का बदला भी 18 दिन बाद लिया गया। देश में इतना गुस्सा था कि, वे ऑपरेशन सिंदूर नहीं तंदूर चाहते थे लेकिन आपने ऑपरेशन सिर्फ तीन दिन में खत्म कर दिया। हम जिसे विश्वगुरु समझ रहे थे, पता चला वो तो व्हाइट हाउस में बैठा है। मैं गर्व महसूस करता हूं सभी विपक्षी दल ने एकजुट होकर कहा कि हम सरकार का साथ देंगे। लेकिन हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए, लेकिन 5 दहशतगर्दों को सरकार पकड़ नहीं पाई।

पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे -गौरव गोगोई

नई दिल्ली। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की गई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की. इसके बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार से कई सवाल पूछे. गोगोई ने कहा कि सरकार यह क्यों नहीं बताती है कि पहलगाम आतंकी हमला कैसे हुआ और आतंकी कैसे घुस आए. गोगोई ने कहा कि सरकार जो 2016 में बातें करती थी, वही बात अब फिर कर रही है. पुलवामा हमले के बाद भी ऐसी बातें कही गई थीं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गौरव गोगोई ने पूछा कि राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा मकसद युद्ध नहीं था, तो क्यों नहीं था. हम पाकिस्तान

अधिकृत कश्मीर कब लेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि उरी अटैक में सबसे दर्दनाक हमला हुआ था. उरी और पुलवामा के बाद पहलगाम में सबसे भयानक हमला हुआ है. पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो बार-बार हमले कर रहा है. गौरव गोगोई ने कहा कि पहलगाम हमले को 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन यह सरकार आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में नहीं ला पाई है. साथ ही कहा कि पहलगाम हमले को लेकर केंद्र सरकार उपराज्यपाल के पीछे नहीं छिप सकती है.

आधार और वोटर आईडी को माना जाए वैध दस्तावेज

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में आधार और मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की अनिच्छा पर सवाल उठाया और कहा कि कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग के बहिष्कार के रवैये पर चिंता व्यक्त की और सत्यापन प्रक्रिया में दोनों दस्तावेजों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि दुनिया का कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है।

बिहार एसआईआर केस : रोक लगाने से इनकार

उन्होंने चुनाव आयोग से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि आधार और ईपीआईसी को पूरी तरह से स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि पंजीकरण फॉर्म में आधार पहले से ही मांगा जा रहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि ईसीआई द्वारा सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है और स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से केवल आधार कार्ड और चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) को बाहर करने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि इन दोनों दस्तावेजों को शामिल करें। कल आपको सिर्फ आधार ही नहीं, बल्कि 11 में से 11 दस्तावेज भी जाली दिख सकते हैं। यह एक अलग मुद्दा है। लेकिन हम सामूहिक बहिष्कार पर हैं। इसे सामूहिक समावेशन होना चाहिए। कृपया आधार को भी शामिल करें। न्यायालय राज्य विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए चुनाव आयोग के 24 जून के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह कदम संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 का उल्लंघन करता है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से विचलित करता है। हालांकि, चुनाव आयोग ने अपने निर्देश का बचाव करते हुए कहा कि उसे संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के तहत ऐसा करने का अधिकार है।

श्रीनगर में सेना का ऑपरेशन 'महादेव', 3 आतंकी मारे गए

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन 'महादेव' के तहत श्रीनगर के पास स्थित दाछीगाम फॉरेस्ट क्षेत्र में तीन आतंकियों को मार गिराया गया है। सुरक्षाबलों को इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दाछीगाम नेशनल पार्क के ऊपरी हिस्से, जो श्रीनगर को त्राल से जोड़ता है, में रविवार देर रात तलाशी अभियान के दौरान अचानक गोलियों की आवाजें सुनाई दीं। इसके बाद सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। तीनों आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि मारे गए आतंकी TRF से जुड़े हो सकते हैं। यह वही संगठन है, जिसने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। दाछीगाम के घने जंगलों को TRF का एक बड़ा ठिकाना माना जाता है।

दावा- इनमें पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा भी

जनवरी 2025 में भी इसी क्षेत्र में TRF का एक अड्डा ध्वस्त किया गया था, जहां सुरक्षाबलों को भारी चुनौती का सामना करना पड़ा था। एनकाउंटर के बाद सोमवार सुबह से पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया है। सुरक्षाबलों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल किसी अन्य आतंकी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय प्रशासन ने आम नागरिकों से इलाके से दूर रहने की अपील की है और ऑपरेशन के दौरान शांति बनाए रखने को कहा है। सुरक्षा एजेंसियां इस ऑपरेशन को आतंक के खिलाफ एक बड़ी सफलता मान रही हैं और इस क्षेत्र में आतंकियों के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

युद्ध की बात करना बंद करें, पाकिस्तान से साथ बात करिए : महबूबा मुफ्ती

श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि अगर भारत को आगे बढ़ना है और समृद्ध होना है तो उसे युद्ध की बात करना बंद कर देना चाहिए तथा बातचीत और सुलह का रास्ता अपनाना चाहिए। पार्टी के 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर शेर-ए-कश्मीर पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग सम्मान के साथ शांति चाहते हैं और जब पाकिस्तान की बात आएगी तो वे देश की विदेश नीति में ''हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, ''मैं भारत सरकार से कहना चाहती हूं कि जम्मू-कश्मीर के लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। हम सम्मान के साथ शांति चाहते हैं, हम दोस्ती के जरिए शांति चाहते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से सुलह का रास्ता अपनाने का आग्रह किया। मुफ्ती ने कहा, ''अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है, तो युद्ध की बात करना बंद करें और (पाकिस्तान के साथ) बातचीत की बात करें। अगर आप दुनिया में अपनी ताकत साबित करना चाहते हैं और चीन से आगे निकलना चाहते हैं, तो बातचीत शुरू करें और सुलह का रास्ता अपनाइए। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होने वाले आगामी एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का जिक्र करते हुए, पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ''मुझे खुशी है कि भारत ने एशिया कप में हिस्सा लेने का फैसला किया है, जबकि हर कोई कह रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। खेलों में भाग लेने दीजिए। मुफ्ती ने कहा कि जब भी जम्मू-कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ शांति और बातचीत की बात करते हैं, तो उन्हें देश की विदेश नीति में दखल न देने की सलाह दी जाती है। पीडीपी प्रमुख ने कहा, ''मैं दिल्ली को बताना चाहती हूं कि जम्मू-कश्मीर के बिना भारत की विदेश नीति क्या है। हमारे बीच युद्ध हुआ, जिससे तबाही हुई। मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि हम विदेश नीति में दखल देंगे और आपको 'बिग ब्रदर बनने के लिए कहेंगे क्योंकि आपकी लड़ाई जम्मू-कश्मीर में लड़ी जा रही है।

लोकतंत्र पर वार एसआईआर के खिलाफ विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन; खड़गे, राहुल, सोनिया और अखिलेश भी हुए शामिल

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सहित इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेता सोमवार को मतदाता सूची के विवादास्पद विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर संसद के मकर द्वार के बाहर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन में सभी विपक्षी दलों ने भाग लिया, नेताओं ने लोकतंत्र पर वार लिखे बैनर और स्टॉप सर लिखी तख्तियां पकड़े हुई थीं, जिसमें सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया गया। प्रदर्शन में असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई और सीपीआई (एमएल) (लिबरेशन) सांसद राजा राम सिंह कुशवाहा भी मौजूद थे, जो एसआईआर के कथित विस्तार पर व्यापक चिंता को दर्शाता है। इस बीच, संसद के चल रहे मानसून सत्र में अपनी ताकत दिखाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल सभी सहयोगी दलों के सांसदों को बुलाया है। भाजपा ने अनुरोध किया था कि सभी एनडीए सांसद आज सुबह 10:00 बजे संसद के मकर द्वार पर उपस्थित रहें।

बाराबंकी के अवसानेश्वर मंदिर में भगदड़, 2 की मौत

जलाभिषेक के दौरान करंट फैलने से हादसा, 29 घायल

बाराबंकी। यूपी में बाराबंकी के अवसानेश्वर महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को भगदड़ मच गई। हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, 29 लोग घायल हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि रविवार रात 2.30 बजे जलाभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में अचानक करंट फैलने से हादसा हुआ। भागने के दौरान लोग एक-दूसरे को कुचलते चले गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना को लेकर डीएम से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। सीएमओ अवधेश यादव ने बताया- हादसे के बाद पुलिसकर्मी एंबुलेंस से 29 लोगों को हैदरगढ़ सीएचसी लेकर आए। 9 को त्रिवेदीगंज और 6 को कोठी सीएचसी भेजा गया। 5 गंभीर घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब तक दो की मौत हुई है। डीएम शशांक त्रिपाठी ने बताया- कुछ बंदर बिजली के तार पर कूद गए थे, जिससे तार टूटकर मंदिर परिसर के टीनशेड पर गिर गया। इसी कारण करंट फैल गया। करंट लगने से प्रशांत कुमार (16) और रमेश कुमार (35) की मौत हुई है। योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अवसानेश्वर मंदिर जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के वक्त लाइन में करीब 3 हजार लोग दर्शन के लिए लगे हुए थे। बता दें, रविवार सुबह हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भी भगदड़ मच गई थी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

कर्नल सोफिया पर टिप्पणी को लेकर मंत्री विजय शाह की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- धैर्य की परीक्षा ले रहे

भोपाल/दिल्ली। भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई। सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया पर अभद्र टिप्पणी को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां मंत्री को कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि वे कोर्ट के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं।न्यायालय ने सुनवाई 18 अगस्त के लिए स्थगित कर दी। केस की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने की। पीठ ने कहा कि मंत्री का व्यवहार कोर्ट को उनकी मंशा पर संदेह पैदा करने के लिए मजबूर कर रहा है। इस पर मंत्री शाह के वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने कहा कि उनके मुवक्किल ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है जो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है और इसे अदालत के रिकॉर्ड में रखा जाएगा। पीठ ने मंत्री द्वारा दिए गए बयानों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल को 13 अगस्त तक रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में बयानों की पड़ताल कर रहे जांच दल ने 87 लोगों से पूछताछ की है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा शाह के इस्तीफे के अनुरोध वाली याचिका पर भी पीठ ने विचार करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि रिट याचिका में पिछले मामलों के बारे में लगाए गए कुछ आरोपों पर तीन सदस्यीय एसआईटी गौर करेगी।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर ममता की शर्त : लोगों को परेशान किया गया, तो नहीं मिलेगी मंजूरी

बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। बीरभूम जिले के बोलपुर में आयोजित एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों ही नहीं, बल्कि गरीबों और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को भी निशाना बना रही है। बनर्जी ने यह भी घोषणा की कि अन्य राज्यों से लौटे उत्पीड़ित बंगाली प्रवासियों की सहायता के लिए एक समर्पित योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने

कहा, ''योजना में उन्हें सुरक्षित लौटने में मदद करने, राशन और नौकरी का कार्ड जारी करने और उन लोगों को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के प्रावधान शामिल होने चाहिए, जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बांग्ला भाषी प्रवासियों का कथित ''उत्पीड़न एक ''सोचा-समझा और ''राजनीति से प्रेरित कृत्य है। हमें सभी उत्पीड़ित बंगाली प्रवासियों के साथ खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अमार पारा, अमार समाधान (हमारा पड़ोस, हमारा समाधान) योजना को सक्रिय रूप से लागू करें, ताकि स्थानीय नागरिकों से जुड़े सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों को सुलझाया जा सके। मुख्यमंत्री की टिप्पणी गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बंगाली प्रवासियों के कथित उत्पीड़न की खबरों के बाद राज्य में राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण माहौल के बीच आई है।

सांसद डिंपल यादव पर टिप्पणी: नंगा शब्द इतना आपत्तिजनक नहीं.., मौलाना बोले- मुझे मुस्लिम होने की सजा मिल रही

नई दिल्ली। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की। उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी और अन्य संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में इस टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जबकि डिंपल यादव ने कहा कि एनडीए को मणिपुर जैसे मुद्दों पर भी इसी तरह सक्रियता दिखानी चाहिए। वहीं, सपा सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अपनी अपमानजनक टिप्पणी पर AIIA अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, संविधान कहता है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं होती है और उन मान्यताओं का प्रचार करना मौलिक अधिकारों में से एक है। नंगा शब्द इतना आपत्तिजनक नहीं है। यह शब्द समाज में इस्तेमाल होता है। शॉर्ट्स पहनने वाली लड़कियों को देखकर हर कोई कहता है कि ये नंगी है। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि उनका सिर और शरीर ढका होना चाहिए था। यह तस्वीर मुसलमानों को अपमानित करने और उन्हें यह दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर क्लिक और अपलोड की गई थी। साजिद रशीदी ने कहा, उनका इस्तेमाल संसद तक पहुंचने के लिए किया जाएगा, लेकिन उनका कोई मूल्य नहीं है। यह जानबूझकर किया गया है और पूरा समुदाय नाराज है। मैंने आवाज उठाई और मेरे खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई। मुझे गालियां दी जा रही हैं, मुझे धमकाया जा रहा है, वे मुझे मेरी बेटी के बारे में धमका रहे हैं। अखिलेश यादव यह कह रहे हैं मेरे पास इस्लाम की ठेकेदारी है।
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो इतना आपत्तिजनक हो कि मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। सड़क पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म होना कोई बड़ी घटना नहीं है, लेकिन एक महिला को आईना दिखाना उनके लिए यह बहुत बड़ी घटना है।

हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, आसिफ इकबाल ने आदेश के खिलाफ दायर की थी याचिका

नई दिल्ली। जामिया नगर इलाके में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा से संबंधित एक मामले में आरोप तय किए जाने के आदेश को आसिफ इकबाल तन्हा ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। ट्रायल कोर्ट ने सात मार्च को तन्हा के विरुद्ध आरोप तय किए थे। अदालत ने तन्हा के साथ शरजील इमाम सहित सह-आरोपितों की याचिकाओं को 30 अक्टूबर के लिए तय कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने इमाम, तन्हा और नौ अन्य लोगों के खिलाफ मामले में आरोप तय किए थे। अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया था कि शरजील इमाम का बयान न केवल भड़काने वाला था, बल्कि हिंसा भड़काने की एक बड़ी साजिश का सरगना भी था।